भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3528
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में पहल

†3528. **श्री गणेश सिंहः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), कोडिंग और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में की गई पहलों का ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन की राज्य-वार और जिला-वार स्थिति क्या है;
(ख) स्मार्ट क्लासरूम, कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित डिजिटल अवसंरचना से सुसज्जित विद्यालयों की राज्य-वार और जिला-वार संख्या कितनी है;
(ग) विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत एआई, कोडिंग और डिजिटल कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों और शिक्षकों की राज्य-वार और जिला-वार संख्या कितनी है;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान विद्यालयों में डिजिटल और प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए वित्तीय आवंटन और व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) उपरोक्त पहल के संबंध में मध्य प्रदेश में, विशेषकर सतना लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा डिजिटल अंतर कम करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भविष्य के लिए तैयार शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है और अधिकांश सरकारी स्कूल राज्य सरकार और उसके निकायों के प्रशासन के अधीन हैं। शिक्षा मंत्रालय मध्य प्रदेश राज्य और विशेष रूप से सतना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षण को बढ़ाने एवं बदलने और प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षण को मजबूत करने के लिए समग्र शिक्षा के तहत पीएम ई-विद्या और दीक्षा जैसी आईसीटी और डिजिटल पहलों को कार्यान्वित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत, वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में प्रस्तुत राज्य की आवश्यकता के अनुसार आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए निधियां प्रदान की जाती है।

पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जिसके तहत देश भर में शिक्षा के लिए बहु आयामी पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत किया जाता है। पीएम ई-विद्या के प्रमुख घटकों को डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की दिशा में भी जोड़ा गया है और इसमें 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं ताकि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) सभी ग्रेडों के लिए क्यूआर कोडे वाली एनर्जेइज्ड पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने हेतु देश का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है। दीक्षा में एक भागीदार के रूप में, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त भारत संस्थाओं ने बहुभाषावाद को सक्षम करते हुए मूल स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.67 लाख से अधिक सामग्री तैयार की है और उनमें योगदान दिया है। यह मंच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपयोग किया जा सकता है, जिससे शिक्षार्थियों को सामग्री डाउनलोड करने और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना सीखना जारी रखने में सहायता मिलती है। दीक्षा पर 836 हितधारकों से अधिक वर्चुअल लैब और 100 वर्चुअल स्किल लैब (हिंदी और अंग्रेजी में 50-50) का उपयोग कर सकते हैं, ये लैब छात्रों को वास्तविक दुनिया की प्रयोगशाला के वातावरण का अनुभव करवाने में मदद करती हैं।

इसके अलावा, सरकार ने दीक्षा पर एआई सक्षम विशेषताएं शुरू की हैं जैसे विज्ञान और गणित के लिए कक्षा 9 और 10 के छात्रों हेतु अलग-अलग अनुकूली शिक्षा (पीएएल), आस्क दीक्षा (पुस्तकों के साथ चैट), वीडियो कीवर्ड सर्च, रीड अलाउड, एआई-आधारित अनुवाद सभी उपयोगकर्ताओं के लिए देश भर में उपलब्ध हैं। सारांश सुविधा उपयोगकर्ता को त्वरित संशोधन के लिए प्रमुख अवधारणाओं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को सारांशित करके पूरे अध्याय का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करती है। पॉडकास्ट सुविधा के हिस्से के रूप में, एआई जनित संवादात्मक चर्चा किसी विषय या अध्याय को समझाने में मदद करती है, जिससे छात्रों को सुनने के माध्यम से सीखने में मदद मिलती है। वार्तालाप में शामिल हों सुविधा के माध्यम से, उपयोगकर्ता प्रश्न पूछने और वास्तविक समय में अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए किसी भी समय पॉडकास्ट वार्तालाप में शामिल हो सकते हैं।

कक्षा XI की मौजूदा एनसीईआरटी कंप्यूटर विज्ञान (अध्याय 3) (https://ncert.nic.in/textbook.php?kecs1=ps-11) और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस (अध्याय 2) (https://ncert.nic.in/textbook.php?keip1=ps-8) की किताबों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी) और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यपुस्तक में एनिमेशन और गेम्स पर एक परियोजना को भी शामिल किया है। इसके अलावा, सीबीएसई कक्षा VI-VIII के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक कौशल मॉड्यूल और कक्षा IX-XII के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैकल्पिक कौशल-आधारित विषय प्रस्तुत करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अपनाने या उसमें बदलाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। वर्तमान में, दीक्षा के पास 9.4+ लाख नामांकन के साथ एआई और डिजिटल लर्निंग पर 59 पाठ्यक्रम हैं।

इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) साक्षरता को बढ़ावा देने और शिक्षार्थियों को एआई-सक्षम भविष्य के लिए तैयार करने हेतु राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम (एनपीएआई) कौशल फ्रेमवर्क के "सभी के लिए एआई" स्तंभ के तहत एआई तत्परता (एसओएआर) कार्यक्रम शुरू किया। प्रारंभ में यह कार्यक्रम तीन मूलभूत एआई शिक्षण पाठ्यक्रमों - एआई टू बी अवेयर, एआई टू एक्वायर और एआई टू एस्पायर, के साथ शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों (कक्षा 6-12) के बीच एआई जागरूकता और बुनियादी क्षमताएं विकसित करना था।

(ख) स्मार्ट क्लासरूम, कम्प्यूटर सुविधा और इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता वाले स्कूलों की संख्या **अनुलग्नक I** के रूप में संलग्न है।

(ग) दीक्षा पोर्टल पर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा 2.29 करोड़ उपयोगकर्ताओं के लिए 579.41 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए गए हैं। अब तक, 1,28,070 लाभार्थियों ने पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (सीटी) संबंधी विभिन्न पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) के अनुसार, दिनांक 05.08.2026 तक की स्थिति के अनुसार एसओएआर कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत किए गए पाठ्यक्रमों के तहत 5,13,385 शिक्षार्थियों को नामांकित किया गया है और 1,00,349 शिक्षार्थियों को प्रमाणित किया गया है और एआई फॉर एजुकेटर्स पाठ्यक्रम के तहत दिनांक 05.08.2026 की स्थित के अनुसार 49,859 शिक्षार्थियों ने नामांकन किया है और 6,296 शिक्षार्थियों को प्रमाणित किया गया है। एसआईडीएच के एसओएआर डैशबोर्ड पर लिंक - https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmI1MzhiOGUtYjc3YS00ZGFiLWEzNjAtYjZlZDdjN2RkMzdiIiwidCI6IjcyNGI4ZWQxLTgxODMtNGNiOS1iNWIwLTFlZDY3YWZlYWNmMSIsImMiOjEwfQ%3D%3D देखा जा सकता है।

(घ) आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं हेतु समग्र शिक्षा के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूलों में डिजिटल और प्रौद्योगिकी-समर्थित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए वित्तीय आवंटन और व्यय को **अनुलग्नक II** के रूप में संलग्न किया गया है।

(ङ): मध्य प्रदेश राज्य में दीक्षा पर 10.47 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता, 338 सक्रिय पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) और 7,100+ ई-सामग्री हैं। पीएम ई-विद्या 200 डीटीएच टीवी चैनल पहल के तहत, मध्य प्रदेश राज्य को पांच समर्पित चैनल (एमपी पीएम ईविद्या 108-112) आवंटित किए गए हैं। सतना जिले में 233 शिक्षकों को एआई का प्रशिक्षण दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 7,405 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, 3,706 में कंप्यूटर सुविधाएं और 5,966 में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। सतना जिले में 234 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, 125 में कंप्यूटर की सुविधा और 109 सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है।

*****

अनुलग्नक I

"उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में पहल" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री गणेश सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 10.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3528 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर सुविधा और इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता वाले स्कूलों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्मार्ट क्लासरूम	कंप्यूटर सुविधा	इंटरनेट कनेक्टिविटी
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	141	297	209
आंध्र प्रदेश	21878	30542	43736
अरुणाचल प्रदेश	511	932	644
असम	11788	42067	43775
बिहार	8892	28753	69807
चंडीगढ़	116	116	116
छत्तीसगढ़	12267	28855	37748
दमन और दीव और दादरा एवं नगर हवेली	290	353	353
दिल्ली	1940	2687	2688
गोवा	113	206	771
गुजरात	25025	33842	33823
हरियाणा	6638	14158	10857
हिमाचल प्रदेश	8378	12398	8973
जम्मू और कश्मीर	2783	6203	8550
झारखंड	5593	29846	20980
कर्नाटक	10728	21100	18007
केरल	3440	4795	4346
लद्दाख	356	478	395
लक्षद्वीप	33	34	34

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्मार्ट क्लासरूम	कंप्यूटर सुविधा	इंटरनेट कनेक्टिविटी
महाराष्ट्र	47550	48518	44220
मणिपुर	385	784	813
मेघालय	166	654	2041
मिजोरम	319	2222	1690
नागालैंड	627	1775	1011
ओडिशा	16738	41243	39693
पुडुचेरी	320	419	419
पंजाब	17352	19182	17339
राजस्थान	17247	29291	45544
सिक्किम	565	767	373
तमिलनाडु	31321	37518	37242
तेलंगाना	9857	25429	19452
त्रिपुरा	1009	3042	1690
उत्तर प्रदेश	37450	113784	58512
उत्तराखंड	5791	15115	10732
पश्चिम बंगाल	2848	17713	13809

स्रोत: यूडीआईएसई+2025-26

अनुलग्नक II

"उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में पहल" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री गणेश सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 10.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3528 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

स्कूलों में डिजिटल और प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट क्लासरूम के लिए समग्र शिक्षा के तहत पिछले तीन वर्षों में अनुमोदित बजट और व्यय का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2023-24, वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 (लाख रूपये में)	
	अनुमोदन	व्यय*
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	225.3	710.4
आंध्र प्रदेश	18259.3	38544.8
अरुणाचल प्रदेश	1744.793	510.8
असम	15404.8	22765.2
बिहार	30941.9	73257.4
चंडीगढ़	316.5	134.1
छत्तीसगढ़	33884.3	1161.1
दमन और दीव और दादरा एवं नगर हवेली	341.9	453.9
दिल्ली	8805.6	1094.2
गोवा	164.6	6.6
गुजरात	5679.3	10813.7
हरियाणा	7819.31	5382.9
हिमाचल प्रदेश	4343.8	8061.6
जम्मू और कश्मीर	10852.9	9588.7
झारखंड	12866.6	8703.1
कर्नाटक	11984	11230.5
केरल	1392.4	0.0

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2023-24, वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 (लाख रूपये में)	
	अनुमोदन	व्यय*
लद्दाख	464.8	229.2
लक्षद्वीप	0.0	0.0
मध्य प्रदेश	52582.1	18057.1
महाराष्ट्र	14664.6	15118.2
मणिपुर	1145.2	2126.6
मेघालय	566.5	649.8
मिजोरम	1760.6	1782.1
नागालैंड	338.5	1272.2
ओडिशा	19535	7813.5
पुडुचेरी	432.4	22.1
पंजाब	20462.3	28402.5
राजस्थान	36188.5	7466.1
सिक्किम	159.1	372.8
तमिलनाडु	48558.3	0.0
तेलंगाना	18483.5	13431.2
त्रिपुरा	3294	6370.5
उत्तर प्रदेश	105332.6	75009.6
उत्तराखंड	2115.8	3128.2
पश्चिम बंगाल	2577.6	142.9

स्रोत: प्रबंध पोर्टल

*व्यय में पिछली जमा राशि शामिल है

****